false and baseless. However in keeping with usual diplomatic practice, Shri Wahi and family returned to India on October 31, 1996.

The assault on Shri Wahi was in apparent retaliation for the apprehension of a Pakistan High Commission official in Delhi on 25th October, 1996 while accepting defence-related documents from an Indian contact. The Pakistani official was declared persona non grata.

The Government of India conveyed its deepest concern to the Pakistani authorities at this criminal incident. The Pakistan High Commissioner was summoned to the Ministry of External Affairs twice and was informed that this abhorrent action was in flagrant violation of all norms of accepted diplomatic practice and the India-Pakistan Code of Conduct for the Treatment of Diplomatic/Consular Personnel. It was demanded that Pakistan should take all necessary steps for the safety and security of our personnel in Islamabad. The same views were conveyed by our High Commission in Islamabad to the Pakistan Foreign office.

Regrettably, it appears that the Pakistani authorities are not taking effective measures to control the intimidating and criminal activities of their intelligence agencies against our officials in Islamabad. We have informed Pakistan that the recurrence of such incidents cannot but negatively impact on India-Pakistan relations.

बिहार में झंझारपुर एक्सचेंज में एस०टी०डी० सिस्टम

1257. **श्री राम देव भंडारी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार टेलीफोन सर्किल के झंझारपुर एक्सचेंज में एस०टी०डी० सिस्टम आमतौर पर खराब रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अगस्त से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान जब एक्सचेंज खराब था तब एस०टी०डी० सिस्टम का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सिस्टम के सुचारु रूप से काम करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) एस०टी०डी० सेवाओं में अगस्त, 96 से 10 नवम्बर, 96 तक व्यवधान उत्पन्न हो गया था।

(ख) यह व्यवधान बिहार राज्य बिजली बोर्ड की 3-फेस इलेक्ट्रिक आपूर्ति से प्रेरण (इन्डक्शन) के कारण हो गया।

(ग) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1996 के दौरान क्रमशः 292 घन्टे, 227 घन्टे तथा 223 घंटे के लिए एस०टी०डी० सेवाओं में व्यवधान हो गया था।

(घ) (i) बिहार राज्य बिजली बोर्ड की सहायता से 3-फेस इलेक्ट्रिक आपूर्ति के पावर-लोड का पुनः वितरण करके इसे संतुलित किया गया।

(ii) एक्सचेंज एम०डी०एफ० की अर्थिंग, के बल शीथ तथा 3-फेस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में सुधार किया गया।

फिजी में भारतीयों के मानवाधिकारों का हनन

1258. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिजी में भारतीय मूल के निवासियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है;

(ख) क्या सैनिक विद्रोह के बाद लागू संविधान के अनुसार भारतीय मूल के निवासियों को फिजी में उनकी संख्या के अनुपात में कहीं कम स्थान व अधिकार दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (ग) सैना द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटने के बाद, 1990 में एक अन्तरिम संविधान लागू किया गया था। जिसमें फिजी के मूल निवासियों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया गया। यह संविधान 1997 तक वैध है। इसमें भारतीय मूल के फिजी राष्ट्रिकों के विरुद्ध निर्देशित जातिवाद और जातीय भेद-भाव को संस्थागत दर्जा प्रदान किया

गया है।

1995 के प्रारम्भ में फिजी की सरकर द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग ने 6 सितम्बर, 1996 को फिजी के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट में फिजी को साम्प्रदायिक राजनीति से समान मताधिकार की ओर ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। हमें यह बताया गया है कि इस रिपोर्ट पर चुनी हुई एक 25 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति विचार करेगी जो जुलाई, 1997 तक संसद में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

भारत सरकार को यह उम्मीद है कि समीक्षा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी जो भारतीय मूल के फिजी राष्ट्रिकों सहित फिजी के सभी राष्ट्रिकों को स्वीकार्य हो। हम संवैधानिक सुधारों की उस प्रक्रिया को समझ रहे हैं जो आरम्भ हो चुकी है और यह आशा करते हैं कि आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन एक ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे भारतीय मूल के फिजी लोगों के आकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी।

भारत सरकार भारतीय मूल के फिजी राष्ट्रिकों के खिलाफ जातीय भेदभाव के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अर्थात् राष्ट्र मण्डल शिखर सम्मेलनों, संयुक्तराष्ट्र महासभा के सत्रों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करने के लिए बराबर कार्रवाई करती रही है। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, अलेक्जेंडर डाउनर की अक्तूबर, 1996 की हाल की यात्रा के दौरान, हमने यह उम्मीद जताई है कि आस्ट्रेलिया फिजी सरकार और प्रमुखों की परिषद् पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि विदेश के लिए सच्चे अर्थों में गैर-जातिगत भेद-भाव वाला संविधान स्वीकार कर सकें।

Waiting List of Phones in Ludhiana, Punjab

1259. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of persons who are in the waiting list for telephones in Ludhiana district of Punjab as on 30th October, 1996;

(b) the steps being taken or proposed to be taken by Government to clear the waiting list?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The number of persons who are in the waiting list for telephones in the District Ludhiana of Punjab as on 30th October, 1996 is 60023.

(b) The following exchanges are proposed to be commissioned during 1996-97, to clear about 50% of the Waiting List.

Sl. No.	Name of Station	Type of System	Capacity
1.	Ludhiana	FETEX-150	40k
2.	-do-	OCB-283	30k
3.	-do-	NEC	20k
4.	Halwara (Ld)	C-DOT 512P	.5k
5.	Issru (LD)	C-DOT 512P	.5K

The remaining 50% waiting list is likely to be cleared during 1997-98.

Extension of Beat From Nagarcoil to Madurai

1260. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any steps are being taken in regard to extension of beat in MA 34 Section from Nagarcoil to Madurai (Moilsenice) by Chief Post Master General, Tamil Nadu;

(b) whether the Madurai Post Master General has taken any view in the matter;

(c) if so, the reasons for the delay; and

(d) the measures Government propose to take in this regard?